Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 91-96 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

क्षेत्रीय राजनीतिक दल और आर्थिक परिवर्तन की राजनीति

जय कुमार मिश्रा[1]

[1]अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिंगरामऊ,जौनपुर,उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

भारत में एक सामान्य स्वीकृति के रूप में यह माना जाता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं हैं। भारतीय लोकतंत्र के सम्यक संचालन में ये बाधा बनते हैं और अर्थव्यवस्था का विकास इनके कारण दुष्प्रभावित होता है। आरंभ से ही यह मान्यता भी रही है कि भारत के राज्यों के लिये उसी दल का सरकार राज्य में भी होना चाहिये जिस दल की सरकार केन्द्र में हो इससे त्वरित विकास को गति प्राप्त होती है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन स्थापित मान्यताओं को पुर्नमूल्यांकित करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न राज्यों जिनमें क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सरकारें हैं उनके जी डी पी का सकल राष्ट्रीय जी डी पी से तुलना के आधार पर समकालिक भारतीय राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की महात्वाकांक्षाओं ने राज्यों में आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान किया है।

KEYWORDS: *राजनीतिक दल, संविद सरकारें, जी डी पी, संघवाद*

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का संघात्मक प्रतिमान 1950–1967 ई. तक केन्द्र एवं राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की प्रधानता होने के कारण 'सहयोगी–संघवाद' के रूप में प्रगट हुआ। इस अवधि में केन्द्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को 'पारिवारिक–विवाद' की भाँति हल कर दिया जाता था क्योंकि दोनो जगह एक ही राजनीतिक दल की सरकार थी। इस कालक्रम में केन्द्र सरकार ने राज्यों के औद्योगिक विकास को तीव्र करने और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया। 1960 के दशक में 'हरित–क्रान्ति' और लघु उद्योगों के विकास के कारण देश में रोजगार एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई, इससे उत्पन्न सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों ने एक ऐसे अभिजात्य वर्ग को जन्म दिया जो अपनी बहुआयामी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करना शुरू किया। इस नवीन वर्ग की मनःस्थिति भाँपकर ही केन्द्र सरकार ने अपनी 'समाजवादी नीतियों' के अन्तर्गत औद्योगिक घरानों का बैंको पर तथाकथित प्रभुत्व समाप्त करने के लिए 1969 ई में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1970 में प्रीवी–पर्स को बन्द कर अपनी 'अमीर और उद्योगपतियों की सरकार' वाली छवि को बदलने का प्रयास किया।

इस वर्ग की राजनीतिक सक्रियता के परिणामस्वरूप 1967 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओड़ीसा, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों में भिन्न–भिन्न क्षेत्रीय दलों की गैर–कांग्रेसी सरकारें बनी। अब केन्द्र एवं राज्यों में अलग–अलग राजनीतिक दलों की सरकार होने से राजनीतिक और विचारधारागत टकराव आरम्भ हुए। इन दलों नें पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पारदशी एवं लोकतांत्रिक बनाने की माँग की और अपने–अपने राज्यों की 'विशेष आवश्यकताओं' को केन्द्र द्वारा अपनी प्राथमिकता–सूची में सम्मिलित करने का दबाव डालना शुरू किया। इन्हीं बदलती हुई दशाओं में 1969 ई में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पहली बार 'विशेष–राज्य' का दर्जा देना प्रारम्भ किया। अब केन्द्र–राज्य सम्बन्ध 'सहयोगी' की जगह 'सौदेबाजी' के हो गए। यहीं से वह युग आरम्भ होता है जब वित्त आयोग और योजना आयोग जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं में इकाई–राज्यों की प्रभावशाली उपस्थिति प्रारम्भ हुई और क्षेत्रीय दलों की राजनीति ने एक नए युग में प्रवेश किया।

यदि क्षेत्रीय दलों का ऐतिहासिक परिप्रक्ष्य में संक्षिप्त विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति में मौलिक अंतर है। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल डी.एम.के. का अस्तित्व तमिल भाषा एवं संस्कृति की उत्तर भारतीय हिन्दी भाषा–भाषियों के प्रभाव से सुरक्षा पर टिका है। एन. टी. रामाराव द्वारा 1982 में बनाए गए तेलगूदेशम् के निर्माण का आधार भी तेलगू संस्कृति की शुद्धता, उसका देशव्यापी प्रसार और उत्तर भारतीयों के आगमन एवं हिन्दी भाषा की बढ़ती प्रभावकारिता को रोकना था। इसी प्रकार महाराष्ट्र की शिवसेना भी उत्तर भारतीयों को 'मराठी मानुष' और मराठी भाषा के हितों के विरूद्ध समझती रही है। इन तीनों ही दक्षिण भारतीय दलों की राजनीतिक यात्रा अपनी–अपनी क्षेत्रीय भाषा–संस्कृति को उत्तर भारतीयों एवं हिन्दी के प्रभाव से बचाने को लेकर प्रारम्भ हुई थी। वर्तमान में उत्तर भारत में सक्रिय क्षेत्रीय दलों का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि इन दलों नें जाति या पृथक राज्य की माँग या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की क्षेत्रीय विकास के प्रति उदाशीनता को आधार बनाकर अपनी यात्रा प्रारम्भ की थी। इन दलों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकदल, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू), झारखण्ड में झारखण्ड मुक्ति

1: Corresponding Author

मोर्चा, ओड़ीसा में बीजू जनता दल आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी दलों का वोट–बैंक वह सामाजिक वर्ग था जो स्वातन्त्रयोत्तर भारत में राजनीतिक पहिचान बनाने के लिए छटपटा रहा था, इन क्षेत्रीय दलों ने राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इस वर्ग को एक नयी पहिचान दी। क्षेत्रीय दलों ने आपस में मिलकर 1996 में देवगौड़ा जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार बनाई और इस बात को स्थापित किया कि क्षेत्रीय दल अब भारतीय राजनीति के निर्धारक बन गए हैं। यही वह प्रस्थान बिन्दु है जहाँ प्रत्येक क्षेत्रीय नेता स्वयं को राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिष्ठित करने की मंशा पालने लगा। राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए अपनी क्षुद्र क्षेत्रीय राजनीतिक आकांक्षाओं का परित्याग या उन्हें छिपाना आवश्यक हो गया अन्यथा भारत के अन्य प्रदेशों के लोग ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं कर पाते।

2000ई. के बाद हम क्षेत्रीय दलों की प्रवृत्तियों में एक महत्वपूर्ण अंतर पाते हैं। पहले क्षेत्रीय दल जाति, भाषा या पृथक राज्य जैसे नकारात्मक मुद्दों की राजनीति करते थे लेकिन अब वे इन मुद्दों को छोड़कर वैश्वीकरण के लाभों का दोहन करने और समावेशी विकास की बात करने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ने के बाद पिछले 15 वर्षों में सभी सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल इस बात को समझ चुके हैं कि जनता का ध्यान नकारात्मक मुद्दों से हटाकर, विकास के लिए सभी सम्भव एवं सार्थक पहल करना बदलते हुए परिवेश में उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्षेत्रीय दल अब हिंसक तरीके से जाति, भाषा, संस्कृति या पृथक राज्य की राजनीति छोड़कर अपने–अपने क्षेत्र के बुनियादी ढॉचे के विकास की प्रतिबद्धता से स्वयं को जोड़ चुके हैं।

क्षेत्रीय दलों ने यह समझ विकसित कर ली है कि वैश्वीकरण के युग में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय एवं उपभोग स्तर बढ़ाना, क्रय क्षमता एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना आदि उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए। अपने इन्हीं 'नवीन राजनीतिक मूल्यों' के आघार पर आज क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को सफलतापूर्वक चुनौती दे रहे हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्थायी चरित्र बन गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की लहर होने के बाद भी तमिलनाडु में कुल 39 सीटों में से 37 सीट ए.आइ.डी.एम.के. को, उड़ीसा की कुल 21 सीटों में से बीजू जनता दल को 20 सीटें और प. बंगाल की कुल 42 सीटों में से 34 सीटें तृणमूल कांग्रेस को प्राप्त हुई–यह सभी क्षेत्रीय दल हैं। ये सभी वे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होनें अपने राज्यों में औद्योगिक उत्पादन एवं आधारभूत ढ़ॉचों के निर्माण में उल्लेखनीय काम किया है। इन सभी क्षेत्रीय दलों ने पिछले कम–से–कम 2 विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय दलों को परास्त किया है। इससे सिद्ध होता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रति जनता के मन में सकारात्मक जगह सुनिश्चित हो गयी है और वह राष्ट्रीय दलों के स्थान पर एक ठोस विकल्प बन चुके हैं।

उत्तर प्रदेश से अपनी बात प्रारम्भ करते हुए यदि पिछले 10 वर्षों से सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दलों की वैश्वीकरण के संदर्भ में राजनीतिक प्राथमिकताओं एवं तत्सम्बन्धी गतिशीलता का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि बहुजन समाज पार्टी (2007–2012ई.) और समाजवादी पार्टी (2012 से अब तक) दोनो ही क्षेत्रीय दलों का वैश्वीकरण के प्रति उत्साहजनक एवं सकारात्मक व्यवहार रहा है। 2009 ई. में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 27 अक्टूबर,2009 को मुम्बई में 'इन्वेस्ट यू.पी. नामक गोष्ठी आयोजित की जिसमें टाटा समूह, अम्बानी बंधु महिन्द्रा ऐण्ड महिन्द्रा, जे.पी.ग्रुप, डी.एल.एफ., लैंको एनर्जी आदि जैसे देश के 100 बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों को तत्कालीन उ.प्र. सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीतियों, राज्य में निजी निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्र और प्रदेश में उपलब्ध आधारभूत ढॉचों एवं संसाधनों की जानकारी दी गई। सरकार ने उस सम्मेलन में यह भी घोषणा की कि प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया 120 दिन से घटाकर 90 दिन कर दी जाएगी।

वर्ष 2012 में प्रदेश का नेतृत्व बसपा के स्थान पर समाजवादी पार्टी के हाथ में आ गया इस क्षेत्रीय दल की सरकार ने भी आधारभूत ढॉचे का विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों के प्रसार को अपनी मूल नीतियों में शामिल करते हुए 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना प्रारम्भ किया। उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कहा कि 500 करोड़ रु. से अधिक पूॅजी निवेश करने पर स्टाम्प ड्यूटी, बिजली तथा करों की दरों में रियायत की जाएगी। द्रुतगामी परिवहन सेवा के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ना और मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे 'इन्वेस्टर्स–मीट' और स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा विदेश दौरा करके विदेशी निवेशकों को प्रदेश में आकर पूॅजीनिवेश करने का आमंत्रण देने का असर अब दिखने लगा है। 14जून,2015 को सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हेतु ही एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाली मेगा परियोजनाओं की विभिन्न इकाइयों पर लगने वाले करों को संशोधित करने का, कच्चे माल की खरीद पर लगने वाले 'वैट' की अगले 10 वर्षों तक 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति स्वयं करने का निर्णय लिया है और मेगा परियोजनाओं की त्वरित अनुमति के लिए 'पिकप' को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है। 19 नवंबर,2015 को सरकार ने यह तय किया कि 'मेक इन यू.पी. के अन्तर्गत सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को लगाने के लिए सरकार ऑनलाइन अनुमति देगी, औद्योगिक स्वीकृतियॉ देने के लिए 'एकल मेज' व्यवस्था लागू होगी और जमीनों के अधिग्रहण के लिए नियमों को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। यह सभी कार्य उन क्षेत्रीय दलों के

हैं जो वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने एवं उत्पन्न अवसरों को भुनाने के लिए जागरूक हैं। इनके कार्यों से उत्तर प्रदेश की जी.एस.डी.पी. में आशातीत वृद्धि हुई है, इसे सारणी 1 में दिखाया गया है। इस सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि, पिछले 7 वर्षों में 3 वर्ष (2008–09, 2012–13 और 2013–14) ऐसे रहे हैं जिनमें उ.प्र. की जी.एस.डी.पी. राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। उ. प्र. को कभी भारत के 'बीमारू'[1] राज्यों में शामिल किया जाता था लेकिन आज यह 'सेकुलर ग्रोथ रेट'[2] के युग में प्रवेश कर चुका है।

(सारणी 1)

2004–05 के स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि की राष्ट्रीय वृद्धि से तुलना (2007 से 2014)

वर्ष	उ0प्र0	भारत
07–08	7.32	9.32
08–09	6.99	6.72
09–10	6.58	8.59
10–11	7.86	8.41
11–12	5.57	6.69
12–13	5.92	4.47
13–14	5.14	4.74

तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल ए.आई.डी.एम.के. ने भी वैश्वीकरण के युग में अवसरों को भुनाने के लिए सफल प्रयास किए हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया था कि, पार्टी राज्य में खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश का विरोध करेगी लेकिन विनिर्माण एवं आधारभूत ढाँचों में इसका समर्थन करेगी। तमिलनाडु पिछले 15 वर्षों में देश का 5वॉं सर्वाधिक विदेशी पूँजी निवेश आकर्षित करने वाला राज्य रहा है। तमिलनाडु 2014–15 में भारत की कुल जी.डी.पी. में 8.16 प्रतिशत का योगदान करके तीसरे स्थान पर रहा, उसी वर्ष तमिलनाडु को 'इकोनामिकली फ्री स्टेट' का पुरस्कार भी मिला। विदेशी पूँजी निवेश को आकृष्ट करने के लिए भारत के अन्य इकाई राज्यों की भॉंति तमिलनाडु ने भी 9–10 सितम्बर,2015 को अपने प्रथम 'तमिलनाडु वैश्विक निवेश सम्मेलन' का आयोजन किया जिसमें एसोचैम, सी.आई.आई. एवं फिक्की जैसे औद्योगिक संगठन और 9 विदेशी राज्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की सफलता के लिए राज्य सरकार ने विदेश में 11 स्थानों पर और देश के विभिन्न राज्यों में 13 स्थानों पर रोड शो आयोजित किए थे। इस आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार ने औद्योगिक घरानों के साथ 100 सहमति–पत्रों पर हस्ताक्षर किए और 1लाख करोड़ रु. के निवेश को मंजूरी दी। पार्टी के पिछले 5 वर्षों के शासन में राज्य की जी.एस.डी.पी. निरन्तर बढ़ रही है, इसे सारणी 2 में देखा जा सकता है। यह सारणी बताती है कि, पिछले 7 वर्षों में 4 वर्ष (2009–10, 2010–11, 2011–12 और 2013–14) ऐसे रहे हैं जिसमें राज्य की जी.एस.डी.पी. राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि 2009–10 और 2010–11 में राज्य में क्षेत्रीय दल के रूप में द्रमुक का शासन था और 2011 के विधानसभा चुनावों में द्रमुक को हराकर अन्नाद्रमुक ने सत्ता प्राप्त किया था एवं वह भी क्षेत्रीय दल ही है।

(सारणी 2)

2004–05 के स्थिर मूल्यों पर तमिलनाडु के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि की राष्ट्रीय वृद्धि से तुलना (2007 से 2014)

वर्ष	तमिलनाडु	भारत
07–08	6.13	9.32
08–09	5.45	6.72
09–10	10.83	8.59
10–11	13.12	8.41
11–12	7.39	6.69
12–13	3.39	4.47
13–14	7.29	4.74

ओड़ीसा में क्षेत्रीय दल के रूप में बीजू जनता दल एक लम्बे समय से (2000ई. से अब तक) अपनी सार्थक, सशक्त एवं प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस क्षेत्रीय दल की राजनीतिक लोकप्रियता और वैश्वीकरण के युग में 'आर्थिक समझ' समय के साथ बढ़ती चली गयी है। गरीबी रेखा से लोगों को बाहर करने, आपदा प्रबन्धन करने (विशेषकर 2013 में आए फेलिन चक्रवात से निपटने के प्रयास) और बच्चों के ड्राप–आउट रेशियो में राज्य सरकार ने अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2 लाख एकड़ का 'भूमि बैंक' विकसित किया है जहॉं खनिजों एवं संसाधनों की बहुलता है। राज्य सरकार ने विदेशी पूँजी निवेश और औद्योगिक उत्पादन गतिविघियॉं बढ़ाने के लिए 2016 ई. में निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। ओड़ीसा सरकार की इन प्रगतिशील नीतियों से विनिर्माण क्षेत्र में जो तेजी आयी उससे लोगों की क्रय–क्षमता बढ़ी है एवं उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद मिली है। राज्य की वर्ष 2000 की जी.एस.डी.पी. की तुलना यदि 2014–15 से की जाय तो ज्ञात होगा कि, 15 वर्षों में इसमें मुद्रा के स्तर पर 6.5 गुना की वृद्धि हो चुकी है, ओड़ीसा ने 2013–14 में 5.60 प्रतिशत और 2014–15 में 7.87 की वार्षिक वृद्धि प्राप्त की, यह दोनो ही वृद्धि उस वर्ष के राष्ट्रीय औसत से अधिक है– देखें, सारणी 3।

(सारणी 3)

2004–05 के स्थिर मूल्यों पर ओड़ीसा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि की राष्ट्रीय वृद्धि से तुलना (2007 से 2014)

वर्ष	उड़ीसा	भारत
07–08	10.94	9.32
08–09	7.75	6.72
09–10	4.55	8.59
10–11	8.01	8.41
11–12	3.78	6.69
12–13	8.09	4.47
13–14	5.60	4.74

बिहार में पिछले 10 वर्षों से क्षेत्रीय दल का शासन होने के बाद भी बिहार में विदेशी पूँजी निवेश बढ़ा है, रोजगार के अवसरों एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में तेजी आयी है और देश के जी.डी.पी. में बिहार का योगदान निरन्तर बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में बिहार की जी.एस.डी.पी. में वृद्धि का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से हमेशा डेढ से दो गुना अधिक रहा है। नितीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन ने 2015 के राज्य विधान सभा चुनावों में भारी सफलता प्राप्त की, कुछ विश्लेषकों ने इसे 'लालू की राजनीतिक विजय' कहा तो कुछ ने इसे 'लालूवादी राजनीति का पुनरुत्थान' कहा लेकिन निष्पक्षतः कहें तो यह नितीश कुमार के विकास कार्यों का प्रभाव है कि कभी उनके धुर विरोधी रहे लालू यादव को उनकी शरण में आना पड़ा। विदेशों में बसे बिहारी भाइयों को बिहार में पूँजी निवेश के लिए प्रेरित कर वैश्वीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम एक क्षेत्रीय दल के नेता के रूप में नितीश ने बखूबी किया है, इससे उन्हें स्वयं एक राष्ट्रीय पहिचान मिली है। बिहार में पिछले 10 वर्षों से क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री के रूप में नितीश कुमार का शासन रहा है और यदि 2005–06 से 2014–15 तक के जी.एस.डी.पी. की वार्षिक वृद्धि–दर का विश्लेषण किया जाय तो उसमें निरन्तर 'तीव्र विकास दर' पाई जा रही है (देखें सारणी 4)। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि, पिछले 7 वर्षो में 5 वर्ष (2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13 और 2013–14) ऐसे रहे हैं जिसमे बिहार की जी.एस.डी.पी. राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है। वैश्वीकरण के युग में बिहार अब 'बीमारू' राज्य की पहिचान से बाहर आने का सार्थक एवं सफल प्रयास कर रहा है (देखें सारणी 4)।

(सारणी 4)

2004–05 के स्थिर मूल्यों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि की राष्ट्रीय वृद्धि से तुलना (2007 से 2014)

वर्ष	बिहार	भारत
07–08	5.55	9.32
08–09	14.54	6.72
09–10	5.35	8.59
10–11	15.03	8.41
11–12	10.29	6.69
12–13	10.73	4.47
13–14	9.92	4.74

इसी प्रकार पश्चिम बंगाल और जम्मू–कश्मीर में भी क्षेत्रीय दलों की ही सरकारें रही हैं ओर इन्होंनें भी क्षेत्रीय विकास, पूँजी निवेश और आधारभूत–संरचनाओं के संदर्भ में प्रशंसनीय कार्य किया है। जम्मू–कश्मीर की स्थितियॉं कुछ मामलों में भिन्न होने के बावजूद भी वह विकास की ओर अग्रसर है, इसका अद्यतन प्रमाण यह है कि, 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के बीच राज्य की जी.एस.डी.पी. राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है (देखें, सारणी 5)।

(सारणी 5)

2004–05 के स्थिर मूल्यों पर जम्मू–कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि की राष्ट्रीय वृद्धि से तुलना (2007 से 2014)

वर्ष	जम्मू कश्मीर	भारत
07–08	6.40	9.32
08–09	6.46	6.72
09–10	4.50	8.59
10–11	5.65	8.41
11–12	7.95	6.69
12–13	4.49	4.47
13–14	5.18	4.74

यदि हम उपरोक्त वर्णित क्षेत्रीय दलों की सरकारों की पिछले 4 वर्षों की नॉमिनल जी.डी.पी.[3] की तुलना राष्ट्रीय नॉमिनल जी.डी.पी. से की जाय तो हम इन राज्यों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते (देखें, सारणी 6)।

(सारणी 6)

क्षेत्रीय दलों की सरकारों की पिछले 4 वर्षों की नॉमिनल जी.डी.पी.[3] की तुलना राष्ट्रीय नॉमिनल जी.डी.पी.

राज्य	10– 11	11– 12	12– 13	13– 14
उत्तर प्रदेश	14.67	13.14	13.24	15.28
तमिलनाडु	21.92	13.75	11.90	14.22
ओड़ीसा	21.22	8.63	19.05	12.90
बिहार	25.39	21.06	26.96	25.00
जम्मू– कश्मीर	20.02	13.24	14.93	15.54
पश्चिम बंगाल	15.56	16.76	15.23	14.14
भारत	**18.66**	**15.77**	**11.88**	**11.54**

उपरोक्त ऑकड़े एवं विश्लेषण यह बताने में सक्षम हैं कि, वैश्वीकरण के लाभों का दोहन करने में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वे अब अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ाव की ओर तेजी से बढ रहे हैं। क्षेत्रीय दल अब अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर केन्द्र सरकार से बिना हिचकिचाए खुली प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने लगे हैं। तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में श्रीलंका में बसे तमिलों के प्रति वैचारिक–व्यावहारिक दृष्टिकोंण किसी भी दल के अस्तित्व एवं भविष्य का निर्धारक बन जाता है। वहॉ सत्ता प्राप्त करने के लिए दोनो ही प्रमुख क्षेत्रीय दल (करुणानिधि के नेतृत्व में द्रमुक और जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक) निरन्तर श्रीलंका मे तमिलों पर होने वाले अत्याचार का मुद्दा उठाते रहे हैं तथा इसे लेकर केन्द्र सरकार पर निरन्तर दबाव डालते रहे हैं।

23 जनवरी,2009 को तत्कालीन द्रमुक सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार से मॉग करते हुए कहा कि, वह श्रीलंका सरकार से तमिलों के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही बन्द करने को कहे। 2013 में तमिलों के ही प्रश्न पर जयललिता ने केन्द्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वर्तमान में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी अपने 2014 के लोकसभा चुनाव के समय पार्टी के घोषणापत्र में कहा था कि, उनकी पार्टी श्रीलंका में युद्धापराधों एवं तमिलों के नरसंहार में शामिल लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दंडित कराने का प्रयास करेगी।

इसी प्रकार कुछ ऐसे भी क्षेत्रीय दल हैं जो अरब–इजराइल संघर्ष के प्रश्न पर अरब जगत का खुला समर्थन और इजराइल की खुली आलोचना करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी में जब भारत ने ईरान के विरुद्ध मतदान किया था या जब अमेरिका ने भारत के साथ 2008 में परमाणु–समझौता किया था तो कुछ क्षेत्रीय दलों ने (उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और जम्मू–कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस) ने भारत सरकार की आलोचना की थी। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर फारूख ने भी अनेक बार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार के विरूद्ध प्रतिक्रिया दी है (उन्होनें पाकिस्तान के साथ की जाने वाली वार्ता में कश्मीरियों को शामिल करने की बात कही थी, अफजल गुरू की फॉसी रोकने की बात कही थी और सलमान रुश्दी को वीजा न देने की बात कही थी)। वस्तुतः आज भी क्षेत्रीय दल अपने 'कोर इन्ट्रेस्ट' को चाहे वह जाति हो या भाषा या क्षेत्र हो या धर्म, उससे बहुत दूर जाने में अभी भी परहेज कर रहे हैं, हॉ लेकिन पहले जैसी कट्टर प्रतिबद्धता भी दिखायी नहीं देती। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव द्वारा दिए गए वक्तव्यों को तथा 2012 के विधानसभा चुनावों में मायावती द्वारा दिए गए वक्तव्यों नें जातीय अस्मिता की आग को हवा देने का कार्य किया था।

भारत में क्षेत्रीय दलों की एक बड़ी प्रवृत्ति यह भी है कि, दल के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रायः अभाव रहा है। दल के नेता कम्पनियों के सी.ई.ओ. की भॉति व्यवहार करते रहना चाहते हैं। इसी कारण क्षेत्रीय दलों में नेतृत्वकर्ताओं की दूसरी या तीसरी पंक्ति बन ही नहीं पाती है। क्षेत्रीय दलों की यह प्रवृत्ति 'डेमोक्रेटरशिप'[4] की द्योतक है जिसमें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की प्रवृत्तियॉ साथ–साथ चल रही हैं। दल के कार्य बाहर से डेमोक्रेटिक प्रतीत होते हैं लेकिन दल के भीतर निर्णय तक पहुॅचने की प्रक्रिया में वाद–विवाद–संवाद का सर्वथा अभाव है। दल के मुखिया का आदेश ही 'निर्णय' का रूप ले लेता है।

कुल मिलाकर, अपनी कुछ कमियों के बावजूद भी क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मजबूत पक्ष बनकर उभरे हैं। इन्होने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का सार्थक प्रयास किया है और संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रीय दलों की परम्परागत प्रतिस्पर्द्धा में सशक्त हस्तक्षेप किया है। विभिन्न इकाई–राज्यों में ये सफलतापूर्वक सत्ता का संचालन कर रहे हैं और सत्ता का संतुलन इनके पक्ष में है। इन्हीं कारणों से आज राष्ट्रीय राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए इनकी शरण लेने लगे हैं। वैश्वीकरण की परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों में भी क्षेत्रीय दलों ने कदम–ताल करना सीख लिया है।

वास्तव में भारत की राजनीतिक व्यवस्था (मजबूत क्षेत्रीय दल एवं राष्ट्रीय दल) और अर्थव्यवस्था (वैश्वीकरण) दोनो को मिलकर ही बदलती हुई विश्व व्यवस्था में भारत की 'जगह' सुनिश्चित करनी होगी। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों दोनो को ही ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना होगा जो केन्द्र में अल्प बहुमत वाली सरकार होने के बाद भी हमारी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा सकें तथा क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित कर सकें। इकाई राज्यों के क्षेत्रीय दलों को यह 'धर्म' भी विकसित करना होगा कि वे 'क्षेत्रीय हितों' के आगे दूरगामी राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कदापि न करें और केन्द्र सरकार का भी दायित्व है कि वह क्षेत्रीय दलों की 'उचित' मॉगों पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दे। आज 'गार' और जी.एस.टी. को लेकर केन्द्र सरकार जिस दबाव में है उसका समाधान क्षेत्रीय दलों को विश्वास में लेकर ही किया जा सकता है।

टिप्पणी

1.'बीमारू' राज्यों की अवधारणा आशीष बोस ने 1980 के दशक के मध्य में दी थी और कहा था कि, इन राज्यों में औद्योगिक गतिविघियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का सर्वथा अभाव है।

2.'सेकुलर ग्रोथ रेट' 4 से 6 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी.पी.) में वार्षिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है। इससे कम विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं को राजकृष्णा ने 'हिन्दू विकास दर' की संज्ञा दी है जिसमें 3 से 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि आती है।

3.नॉमिनल जी.डी.पी. की गणना करते समय मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि जी.डी.पी. में वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत है और मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत है तो वास्तविक जी.डी.पी. हुई 6 प्रतिशत लेकिन नॉमिनल जी.डी.पी. 10 प्रतिशत ही हुई।

4.'डेमोक्रेटरशिप' शब्द का प्रयोग किसी ऐसी सरकार के लिए किया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाने और सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद अपने 'लोक उत्तरदायित्वों' से विमुख हो जाय और स्वयं को कानून से ऊपर मानने लगे। इसलिए ही लार्ड ऐक्टन ने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है।

5.उपरोक्त सभी सारणी में प्रदर्शित ऑकड़े योजना आयोग से लिए गए हैं।

सन्दर्भ

चकवर्ती,विद्युत (1999) : *द चेंजिंग कन्टूर्स आफ फेडरलिज्म इन इण्डिया, : स्ट्रेस एण्ड स्टेटस* इन डी डी खन्ना एण्ड गर्ट डव्ल्यू कुक संपा : प्रिंसिपल्स, पावर्स एण्ड पॉलिटिक्स, मैकमिलन, दिल्ली.

खान, आर सी (1999) : *रीजनल पॉलिटिकल पार्टीजः फेडरल एक्सपीरियेन्स इन इण्डियन पॉलिसी* इन वीजापुर संपा डाइमेन्सन आफ फेडरल नेशन विल्डिंग, नई दिल्ली, मानक पव्लिकेशन

सेन, सुमन्त (1984) : दी अपोजीसन, : प्लेयिंग फार टाइम, *इण्डिया टूडे*, फरवरी 1–15

राव, वी चन्द्रमौलेश्वर (1988) : *फेडरलाइजिंग इण्डियन पालिसीज,– दी रोल आफ तेलगुदेशम पार्टी*, ए स्टडी पेपर प्रजेंटेड इन ए नेशनल सेमिनार आन फिफटी इयर्स आफइण्डियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम–नीड फार रिफार्मस,आर्गनाइज्ड वाइ डिपार्टमेंट आफ पालिटिकल साइंस एण्ड पव्लिक एडमिनिस्टेशन, एस वी यूनिवर्सिटी तिरूपत, मार्च,09.10

राय, हरिद्वार एण्ड विजय कुमार (2007) : *चेजिंग पार्टी सिस्टम एण्ड विटालिटी आफ दी फेडरल स्ट्रक्चर इन इण्डिया* इन फेडरल सिस्टम एण्ड कोएलिशन गवर्नमेंट इन इण्डिया कान्फिलक्ट एण्ड कान्सस इन सेन्टर स्टेट रिलेशन, नई दिल्ली, कनिष्क पव्लिकेशन्स